



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

महकमों के नामों में बदलाव करने के लिए

**#महकमों**

[क.म.१४] #महकमों 'कफुक' फुनक 09 अक्टूबर 2013 को 'क' 20 1934 'क' 1 ए० 1/2 [क.म.१४] क.०६

फो'क; &ल पं

1 र; 1 द हकक द 1 "B व्यं व्यं फं; 1 x, ग] फ 1 1 1 मुद व्यं व्यं [क.म. कु 1 द

फो'क;	1 "B 1 [; क	क'क' पं
		#0
1 ए 1. क 1 xt V द क eY; --- --- ---	&	3075
हकक 1 &foKflr &vod'k] fu; fDr] LFkku &fu; fDr] LFkkuUrj.k] vf/kdj vkj nl j; o; fDr d ukfVI ---	45&52	1500
हकक 1 &d &fu; e] dk; &fof/k; k] vkKk, j] foKflr; k; bR; kfn ft ud k; mUkj k[ k. M d j kT; i ky egkn; j] foHkUu foHkxk; d; v/; {k rFkk jkt Lo i fj "kn u t kjh fd; k ---	31&47	1500
हकक 2 &vkKk, j] foKflr; k] fu; e vkj fu; e fo/kku] ft ud k; dUæh; 1 j dkj vkj vU; j kT; k; dh 1 j dkj k; u t kjh fd; k] gkb d kVI dh foKflr; k] Hkkjr 1 j dkj d; xt V vkj nl j; j kT; k; d; xt V k; d; m) j. k--- ---	&	975
हकक 3 &Lok; U; 'kkl u foHkx dk ØkM&i=] uxj ç' kkl u] ukVhQkbM , fj; k] Vkm u , fj; k , o fuokpu %LFkkuh; fudk; % rFkk i pk; rhj kt vkfn d; fun'k ft Ug; foHkUu vk; Dr k; vFkok ft ykf/kdj; k; u t kjh fd; k ---	&	975
हकक 4 &fun'kd] f' k{kk foHkx] mUkj k[ k. M --- ---	&	975
हकक 5 &, dkmUVUV t ujy] mUkj k[ k. M --- ---	&	975
हकक 6 &fcy] t k; Hkkjr h; 1 l n e; çLr fd, x, ; k çLr fd, t ku; 1 i gy; çdkf'kr fd, x, rFkk fl yDV defV; k; dh fj i kVI --- ---	&	975
हकक 7 &byD'ku deh'ku vkQ bf. M; k dh vufofgr rFkk vU; fuokpu 1 Ecu/kh foKflr; k; --- ---	&	975
हकक 8 &I puk , o; vU; o; fDr d foKki u vkfn ---	&	975
LVkl 1 i pit &LVkl 1 i pit foHkx dk ØkM&i= vkfn ---	&	1425

**Hkkx 1**

विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

**I kekU; i' kkl u vuHkkx**

दिनांक 07 जनवरी, 2013 ई0

**अधिसूचना****प्रकीर्ण**

संख्या: 118/XXXI (13)G-65 (सू0अ0)/2012—श्री राज्यपाल महोदय, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2005) की धारा 27 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

**mÜkj[k.k.M I puk dk vf/kdkj fu; ekoyh] 2012****1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :**

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 है।
- (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

**2. परिभाषाएं :**

2. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में—
  - (क) “अधिनियम” से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है,
  - (ख) “धारा” से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा अभिप्रेत है,
  - (ग) “आयोग” से उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है,
  - (घ) “राज्य सरकार” से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है,
  - (ङ) “बी0पी0एल0” से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे व्यक्ति, जिनकी वार्षिक आय रू0 12,000/—(रू0 बारह हजार मात्र) से कम हो, अभिप्रेत है,
  - (च) “प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी” से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन योजित प्रथम अपील के निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा धारा 19(1) के अधीन नामित अधिकारी से अभिप्रेत है,
  - (छ) ‘सूचना’ से किसी इलेक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई—मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़े सम्बन्धी सामग्री और किसी निजी निकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी, लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है।

**नोट —**

- (एक) मत, सलाह अथवा विचार जो किसी अभिलेख, दस्तावेज या किसी सामग्री के रूप में नहीं है, वह ‘सूचना’ नहीं है।
- (दो) किसी कार्य को जैसे किया गया उसे वैसे क्यों किया गया, अन्य किस रूप में किया जा सकता है, जैसे कार्य को किया गया वह उचित है या नहीं आदि विचार या मत सामग्री के रूप में नहीं होने पर ‘सूचना’ नहीं है।

‘अभिलेख’ में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:—

- (क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाईल,
- (ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिको और प्रतिकृति प्रति,
- (ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिविम्ब या प्रतिविम्बों का पुनरुत्पादन (चाहे व्यक्ति के रूप में हो या न हो); और
- (घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री।

(ज) 'सूचना का अधिकार' से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है:—

(एक) कृति दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

(दो) दस्तावेजों या अभिलेखों की टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;

(तीन) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

(चार) डिस्कट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना।

(झ) उन शब्दों और पदों के, जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में हैं।

### 3. राज्य सरकार द्वारा स्वतः प्रकटन के लिये सूचना विहित करना :

राज्य सरकार समय-समय पर किसी लोक प्राधिकारी अथवा लोक प्राधिकारियों से स्वतः प्रकटन की जाने वाली सूचना राज्य सरकार के गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके विहित कर सकती है। विहित की गयी सूचना का प्रकाशन लोक प्राधिकारी विहित किये जाने के 60 दिन के अन्दर अभिलेख रूप में और इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में करेगा। लोक प्राधिकारी विहित सूचना को प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक करेगा।

### 4. आवेदन की भाषा:

सूचना की प्राप्ति हेतु आवेदन हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि में अथवा अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जायेगा।

### 5. सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया:

(क) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन 'सूचना' प्राप्त किये जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ अनुरोध पत्र दिया जायेगा।

(ख) 'सूचना' के लिए ऐसे अनुरोध पत्र, जिसके साथ निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि प्रस्तुत नहीं की गयी है, पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ग) विभिन्न लोक प्राधिकारियों से उनकी अभिरक्षा में अथवा नियंत्रण में 'सूचना' को प्राप्त करने के लिए समवस्थित लोक प्राधिकारियों के लोक सूचना अधिकारियों अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारियों को निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ पृथक-पृथक अनुरोध पत्र दिये जायेंगे।

(घ) 'सूचना' के लिए अनुरोध ऐसी सूचना के लिए किया जा सकेगा, जो अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन 'सूचना' परिभाषित है और लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण में हैं। सूचना के लिए अनुरोध पत्र द्वारा अधिनियम में परिभाषित 'सूचना' से इतर सूचना यथा प्रश्नों के उत्तर या ऐसी सूचना जिस पर मत स्थिर कर नया निर्णय लेने की आवश्यकता हो, का अनुरोध किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को 'सूचना धारित नहीं है' से अवगत करायेगा।

(ङ) 'सूचना' के लिए अनुरोधकर्ता द्वारा एक ही अनुरोध पत्र में एक से अधिक लोक प्राधिकारियों की अभिरक्षा या नियंत्रण की 'सूचना' की मांग किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की सूचना अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी। अन्य लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित 'सूचना' के लिए अनुरोध पत्र अन्य लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित कर दिया जायेगा। एक से अधिक अन्य लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित 'सूचना' का अनुरोध की दशा में अनुरोधकर्ता को ऐसी 'सूचना' के लिए सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारियों से पृथक से आवेदन करने के लिए कहा जायेगा।

(च) 'सूचना' के लिए अनुरोधकर्ता द्वारा एक ही अनुरोध पत्र में दो लोक प्राधिकारियों से सम्बन्धित सूचना मांगने पर लोक सूचना अधिकारी अपने लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित 'सूचना' यथा प्रक्रिया अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायेगा। अन्य लोक प्राधिकारी का स्पष्ट ज्ञान न होने पर अनुरोध पत्र अन्य लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए अनुरोधकर्ता को सूचित किया जायेगा।

(छ) अनुरोध पत्र में मांगी गयी 'सूचना' का चिन्हीकरण स्पष्ट रूप से न होने की दशा में लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को लोक प्राधिकारी की प्रकटन योग्य 'सूचना' का निरीक्षण करके अथवा अन्यथा चिन्हीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 5 दिन के भीतर करेगा। अनुरोधकर्ता द्वारा 'सूचना' का चिन्हीकरण करके लोक सूचना अधिकारी को अवगत कराने पर 'सूचना' यथा प्रक्रिया निर्धारित अवधि के भीतर दी जायेगी। अनुरोधकर्ता द्वारा 'सूचना' के चिन्हीकरण में लगने वाले समय की 'सूचना' दिये जाने की अवधि में गणना नहीं की जायेगी।

(ज) आवेदक द्वारा मांगी गयी 'सूचना' का अनुरोध अस्वीकार करने की दशा में लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को अनुरोध अस्वीकार के कारण सूचित करेगा। लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को अनुरोध अस्वीकार करने के विरुद्ध अपील करने की समय अवधि तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम, पता आदि विवरण सूचित करेगा।

(झ) आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना उसी 'प्रारूप' में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें उसे मांगा गया है जब तक कि उस सूचना को उपलब्ध कराने में लोक प्राधिकारी के संसाधनों को अनुपाती रूप में विचलित न होती हो अथवा आवेदित सूचना के अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो।

## 6. सूचना हेतु शुल्क :

(क) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन सूचना हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी, लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के वित्त/लेखा अधिकारी के नाम संदेय रु0 10.00 मात्र का शुल्क उचित रसीद की प्रति, नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा:

परन्तु यह कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को कोई शुल्क अनुरोध पत्र के साथ देय नहीं होगा। इस हेतु आवेदक को बी0पी0एल0 कार्ड की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

(ख) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन सूचना की लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क सूचना दिए जाने हेतु लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखा अधिकारी के नाम संदेय निम्नलिखित दरों के अनुरूप शुल्क उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा, अर्थात्,

(एक) ए-3 या ए-4 आकार के पृष्ठ(छायाप्रति या तैयार सूचना) हेतु रु0 2.00 (दो रुपये मात्र) प्रति पृष्ठ और इससे बड़े आकार के पृष्ठ हेतु वास्तविक लागत,

(दो) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम घंटा हेतु कोई शुल्क संदेय नहीं होगा, तदुपरान्त प्रत्येक 15 मिनट अथवा उसके भाग हेतु रु0 5.00 मात्र(पांच रुपये मात्र) का शुल्क संदाय किया जाना होगा,

(तीन) प्रतिरूप एवं नमूनों की वास्तविक लागत का संदाय किया जाना होगा।

(ग) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा(5) के अधीन सूचना छपे या इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना दिए जाने हेतु लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखाधिकारी के नाम देय निम्नलिखित दरों के अनुरूप शुल्क, उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा, अर्थात्

(एक) डिस्कट अथवा फ्लॉपी पर सूचना दिए जाने हेतु रु0 50.00 मात्र (पचास रुपये मात्र) प्रति फ्लॉपी/डिस्कट: और

(दो) किसी मुद्रित प्रकाशन की दशा में, उसका निर्धारित मूल्य या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति पृष्ठ के लिए रु0 2.00 मात्र(दो रुपये मात्र)।

(घ) बी0पी0एल0 श्रेणी के व्यक्तियों के सूचना अनुरोध पर शुल्क हेतु निम्नलिखित व्यवस्था होगी:-

(एक) यदि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना उसके (बी0पी0एल0 श्रेणी के) स्वयं से या उसके परिवार से सम्बन्धित हो, तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी।

(दो) यदि सूचना/बी0पी0एल0 श्रेणी के अनुरोधकर्ता या उसके परिवार के सदस्य से भिन्न व्यक्ति से सम्बन्धित हों, और सूचना 50 छाया पृष्ठों (ए-4 साईज के) या तैयार करने में रुपये 100 के व्यय में दी जा सकती है तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी। उसके उपरान्त सशुल्क सूचना उपलब्ध करायी जाएगी। एक लोक प्राधिकारी से एक माह में उक्त से अधिक पृष्ठों की सूचना निःशुल्क निर्गत नहीं की जायेगी।



(तीन) यदि सूचना 50 छाया पृष्ठों से अधिक की है या उसमें रुपये 100 से अधिक खर्च आता है तो धारा 7 की उप-धारा (9) के अधीन कारण अभिलिखित कर, आवेदक से कार्यालय में अभिलेखों, आस्तियों के अवलोकन करने का निवेदन किया जायेगा। सूचना अभिलेख रूप में या इलैक्ट्रॉनिक रूप में मांग किये जाने पर 'सूचना' का लागत के समतुल्य शुल्क अदा करने पर ही अभिलेख रूप अथवा इलैक्ट्रॉनिक रूप में 'सूचना' निर्गत की जा सकेगी।

## 7. राज्य लोक सूचना अधिकारी के दायित्व:

(क) लोक सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन अनुरोधकर्ता को लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र प्राप्त होने से 30 दिन की निर्धारित अवधि में वांछित सूचना देने हेतु उत्तरदायी होगा।

(ख) अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी सूचना में से कुछ 'सूचना' किसी अन्य लोक सूचना अधिकारी से सम्बन्धित हो, तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा धारा 6(3) के अधीन अनुरोध पत्र को सम्बन्धित लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित कर अनुरोधकर्ता को सूचित किया जायेगा।

(ग) नियम 5 के खण्ड (ख) व (ग) में उल्लिखित अतिरिक्त शुल्क हेतु अनुरोध कर्ता को यथासंभव अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर सूचित किया जाएगा।

(घ) तीसरे पक्ष की सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिनियम की धारा 11 के अधीन तीसरे पक्ष से अनापत्ति प्राप्त की जाएगी। यदि तीसरे पक्ष की आपत्ति 10 दिन के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो लोक सूचना अधिकारी सूचना देने पर विचार कर सकेंगे।

(ङ.) अधिनियम की धारा 8 में उल्लिखित सूचनाएं जिन्हें प्रकटन से छूट है, को लोक सूचना अधिकारी अनुरोध किये जाने पर अनुरोधकर्ता को उपलब्ध नहीं करायेगा।

(च) निजी सूचनाएँ, जिसका प्रकटन का लोक गतिविधि या लोक हित से सम्बन्ध नहीं है अथवा जिसका प्रकटन किसी व्यक्ति की निजता में अवांछित अतिक्रमण है, का प्रकटन नहीं किया जायेगा सिवाय तब जब लोक सूचना अधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि वृहत्तर लोक हित में निजी सूचनाओं के प्रकटन न्यायपूर्ण हैं।

(छ) लोक सूचना अधिकारी अनुरोध की गयी 'सूचना' के उस अंश को प्रकटन करेगा, जो प्रकटन से छूट प्राप्त नहीं है। प्रकटन से छूट प्राप्त अंश का अनुरोधकर्ता को न निरीक्षण कराया जायेगा और न ही निर्गत किया जायेगा।

## 8. विभागीय अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील:

(क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन लोक सूचना अधिकारी के निस्तारण के विरुद्ध अपील किये जाने पर अपीलकर्ता को अपील के साथ अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र के निस्तारण का पत्र, की प्रति संलग्न करनी होगी। अपील पत्र में अपील के आधार स्पष्ट रूप से लिखे जायेंगे। यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि अपीलकर्ता लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं है।

(ख) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता द्वारा दाखिल अपील पर आवश्यकतानुसार लोक सूचना अधिकारी से पक्ष प्राप्त किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर अपीलकर्ता को उपस्थित होने के लिए निर्देश दिये जा सकेंगे और अपीलकर्ता से लिखित पक्ष प्राप्त किया जा सकेगा।

(ग) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील का निस्तारण अधिनियम में उल्लिखित अवधि में किया जायेगा। अपील के निस्तारण के आदेश की प्रति अपीलकर्ता और लोक सूचना अधिकारी को सुलभ करायी जायेगी।

(घ) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी अपील पर विचार करते समय यह समाधान करेंगे कि अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी 'सूचना' प्रकटन की जा सकती है अथवा नहीं। प्रकटन की जा सकने वाली 'सूचना' अनुरोधकर्ता को निर्धारित समय के अन्दर निर्गत की गयी है अथवा नहीं। मांगी गयी वह 'सूचना' जिसका लोक सूचना अधिकारी ने प्रकटन करना अस्वीकार किया है, वह 'सूचना' अधिनियम की धारा 8 के प्राविधानों के अन्तर्गत छूट से प्राप्त है। वह 'सूचना' जिसका प्रकटन धारा 8 के अन्तर्गत छूट प्राप्त नहीं है और अपील तक निर्गत नहीं की गयी है, उस सूचना को लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को यथाशीघ्र निर्गत की जायेगी।

(ड.) आवेदक द्वारा मांगी गयी 'सूचना' का चिन्हीकरण स्पष्ट न होने के कारण 'सूचना' न दिये जाने की स्थिति प्रकट होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी आवेदक को लोक प्राधिकारी के सम्बन्धित अभिलेखों का निर्धारित शुल्क प्राप्त करके निरीक्षण कराकर आवेदक द्वारा चिन्हीत 'सूचना' को निर्धारित शुल्क भुगतान करके दिये जाने के आदेश देगा।

(च) प्रथम अपीलीय अधिकारी इसकी पड़ताल अपील सुनते हुए करेगा कि लोक सूचना अधिकारी ने व्यक्तिगत सूचना प्रकटन करने में अधिनियम की धारा 8(ज) के प्रावधानों के अनुरूप व्यक्तिगत 'सूचना' का प्रकटन करने से मना किया है। लोक सूचना अधिकारी ने ऐसी व्यक्तिगत सूचना जो लोक क्रिया कलाप व हित से सम्बन्ध रखता है या जिससे व्यक्ति की एकान्तता पर अनावश्यक अतिक्रमण नहीं है अथवा जिसका प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है उसे प्रकटन से रोका नहीं है।

(छ) प्रथम अपीलीय अधिकारी अपील के निर्णय में उपरिलिखित उपनियमों में अंकित बिन्दुओं की विवेचना अंकित करेगा तथा जिस 'सूचना' का प्रकटन निषिद्ध नहीं है उस सूचना का प्रकटन करने के लिये लोक सूचना अधिकारी को निर्देश निर्गत करेगा।

(ज) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी लोक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना निर्गत करने के लिए बाध्य नहीं करेगा, जो अधिनियम के अन्तर्गत 'सूचना' नहीं है अथवा प्रकटन से छूट प्राप्त है।

## 9. सूचना आयोग में द्वितीय अपील :

(क) अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के अपील निस्तारण के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष किये जाने पर अपीलकर्ता को द्वितीय अपील पत्र के साथ अनुरोधकर्ता का अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी के अनुरोध पत्र के निस्तारण का पत्र, प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपील के निस्तारण आदेश की प्रति संलग्न की जायेगी। द्वितीय अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

(ख) अपीलकर्ता द्वारा द्वितीय अपील करने पर आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(एक) द्वितीय अपील में संबंधित लोक सूचना अधिकारी व प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को उत्तरदाता बनाया जायेगा। अन्य किसी अधिकारी/प्राधिकारी को द्वितीय अपील में उत्तरदाता नहीं बनाया जायेगा।

(दो) द्वितीय अपील पत्र में अपीलकर्ता द्वारा उल्लिखित आधारों पर लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को लिखित रूप से अपना प्रतिवाद प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(तीन) द्वितीय अपील में आयोग इसकी जांच करेगा कि लोक सूचना अधिकारी ने अनुरोधकर्ता को आवेदित 'सूचना' अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप सुलभ करायी है अथवा नहीं। आयोग द्वितीय अपील में यह भी जांच करेगा कि प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप अनुरोधकर्ता को सूचना निर्गत करने के लोक सूचना अधिकारी को निर्देश दिया या नहीं। लोक सूचना अधिकारी ने 'सूचना' निर्धारित अवधि में निर्गत करी है या नहीं। अनुरोधकर्ता को प्रकटन योग्य सूचना प्रकटन न किये जाने से कोई क्षति हुई या नहीं। अपीलकर्ता को जो क्षति हुई है, उसका मूल्यांकन क्या है। आयोग उक्त बिन्दुओं पर आवश्यक पड़ताल करके द्वितीय अपील का आदेश पारित करेगा।

(चार) द्वितीय अपील में अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी 'सूचना' के निर्धारित समय के अन्दर प्रकटन का मामला ही देखा जायेगा। द्वितीय अपील में किसी जांच का निर्देश नहीं दिया जायेगा।

(पांच) द्वितीय अपील के आदेश में सूचना आयोग यथा आवश्यकता अधिनियम की धारा 19(8) के अनुरूप सूचना के प्रकटन और पहुँच बनाये जाने के लिए निर्देश दे सकेगा।

(छ) द्वितीय अपील के निस्तारण में लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को सुनवायी में उपस्थित होने का निर्देश निर्गत नहीं किया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में कारण अभिलिखित करके लोक सूचना अधिकारी अथवा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को द्वितीय अपील में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकेंगे।

- (सात) आयोग द्वारा द्वितीय अपील की सुनवायी के समय यह समाधान होने पर कि लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की जानी आवश्यक है, लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत कर कारण बताने का अवसर दिया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपना पक्ष रखने अथवा निर्धारित अवधि व्यतीत होने पर आयोग, लोक सूचना अधिकारी पर आवश्यक होने पर शास्ति आरोपित करेगा। लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उक्त कार्यवाही द्वितीय अपील की कार्यवाही से पृथक रूप से की जायेगी।
- (ग) (एक) तीसरे पक्ष की सूचना प्रकटन के मामले में लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आयोग में अपील में अपील पत्र के साथ लोक सूचना अधिकारी का आदेश तीसरे पक्ष की मांगी गयी सूचना, तीसरे पक्ष द्वारा दिया गया कथन संलग्न किया जायेगा। अपील पत्र में अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
- (दो) उक्त उपखण्ड(एक) के अनुसार प्रस्तुत अपील में तीसरे पक्ष को आयोग अपना पक्ष रखने का अवसर देगा।
- (तीन) अपील के निस्तारण के लिये लोक सूचना अधिकारी तथा तीसरे पक्ष को आयोग द्वारा अपील में अपना पक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।
- (घ) आयोग द्वारा निर्गत नोटिस का तामिल निम्नवत् किया जा सकेगा:—
- (एक) स्वयं पक्षकार के माध्यम से;
- (दो) तामिलकर्ता के माध्यम से दस्ती;
- (तीन) साधारण डाक द्वारा; या
- (चार) कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के माध्यम से।
- (पाँच) पावती के साथ पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से।
- किन्तु अग्रतर प्रतिबंध यह है कि खण्ड(पाँच) के अनुसार तामिल प्रथम चार तरीकों से तामिल न होने की दशा में ही किया जायेगा।
- (ङ.) अपीलार्थी या पक्षकारों को सुनवाई के लिए आयोग निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायेगा:—
- (एक) अपीलार्थी या प्रतिपक्ष, जैसी स्थिति हो, आवेदन की प्रक्रिया में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु किसी भी व्यक्ति अथवा अधिवक्ता का सहयोग ले सकेगा।
- (दो) आयोग के आदेश खुले में सुनाये जाएंगे और आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी या सचिव द्वारा लिखित रूप में अभिप्रमाणित किए जाएंगे।

#### 10. धारा 18 के अन्तर्गत आयोग द्वारा कार्यवाही की प्रक्रिया:

(क) आयोग अधिनियम की धारा 18(1) के खण्ड (क) से (च) में उल्लिखित कारणों से की गयी शिकायत की जांच करेगा। द्वितीय अपील में पारित आदेश का अनुपालन कराने के लिए आयोग को शिकायत प्रस्तुत नहीं की जायेगी।

(ख) शिकायत में शिकायतकर्ता स्पष्ट अंकित करेगा कि धारा 18 की उपधारा(1) के खण्ड (क) से (च) में से किस आधार या आधारों पर शिकायत की गयी है।

(ग) शिकायत की प्रति लोक सूचना अधिकारी अथवा लोक प्राधिकारी के प्रमुख, जैसी स्थिति हो, को भेजा जायेगा और शिकायत पर अपना पक्ष लिखित रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(घ) आयोग आवश्यकतानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों का साक्ष्य ले सकेगा, जो शिकायत की जांच के आवश्यक हो। ऐसे अभिलेख मंगा सकता है और निरीक्षण कर सकता है, जो शिकायत की जांच के लिए आवश्यक हो।

(ङ.) आयोग शिकायत की जांच करके दोषी लोक सूचना अधिकारी को दण्डित करने के लिए शास्ति आरोपित कर सकेगा अथवा लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति कर सकेगा।

**11. आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति तथा क्षतिपूर्ति की वसूली:**

(क) लोक सूचना अधिकारी पर अधिरोपित शास्ति अथवा लोक प्राधिकारी पर अधिरोपित क्षतिपूर्ति द्वितीय अपील अथवा शिकायत, यथास्थिति, में पारित आयोग के आदेश के दो माह की अवधि समाप्त होने पर वसूल किया जा सकेगा।

(ख) आयोग लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने पर शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की एक प्रति शास्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ लोक सूचना अधिकारी के लोक प्राधिकारी को उपलब्ध करायेगा, जो आदेश प्राप्त होने पर उसकी पावती आयोग को इस आशय से प्रेषित करेंगे कि वसूली के प्रयोजनार्थ शास्ति को नोट कर लिया गया है।

(ग) आयोग लोक प्राधिकारी पर क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने पर क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की एक प्रति क्षतिपूर्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ स्वयं लोक प्राधिकारी को उपलब्ध करायेगा, जो आदेश प्राप्त होने पर उसकी पावती आयोग को इस आशय से प्रेषित करेंगे कि वसूली के प्रयोजनार्थ क्षतिपूर्ति को नोट कर लिया गया है।

(घ) शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश की प्रति सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को उपलब्ध कराना ही पर्याप्त होगा। खण्ड (ख) व (ग) के अन्तर्गत आयोग को आदेश की पावती प्राप्त होना इस बात का प्रमाण होगा कि लोक प्राधिकारी ने शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने के आदेश को वसूली के प्रयोजनार्थ नोट कर लिया है। पावती प्राप्त होने पर आयोग शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने से सम्बन्धित प्रचलित कार्यवाही समाप्त कर देंगे और इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही अथवा अनुश्रवण नहीं किया जायेगा।

(ङ) खण्ड (ख) व (ग) के अन्तर्गत आयोग से आदेश प्राप्त होने व लोक प्राधिकारी द्वारा उसकी पावती आयोग को प्रेषित करने पर खण्ड (क) के अधीन शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने का उत्तरदायित्व लोक प्राधिकारी का होगा।

(च) लोक प्राधिकारी द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति को वसूल किये जाने, उसे राजकोष में जमा करने अथवा आवेदनकर्ता को भुगतान करने की कार्यवाही, यथास्थिति, ऐसी रीति, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर आदेश जारी कर विहित करे, के अनुसार किया जायेगा।

**12. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति:**

यदि इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार आदेश जारी कर सकेगी, जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन हो।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,  
सचिव।



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## mÜkj k[ k. M I j dkj } kj k i idkf' kr

#Mdh] 'kfuokj] fnukd 09 Qjoj] 2013 b0 %ek?k 20] 1934 'kd I Eor½

Hkkx 1&d

fu; e] dk; &fof/k; k] vkKk, j] foKflr; k bR; kfn ft ud k mÜkj k[ k. M d j kT; i ky egkn; j] fofHkUu fofHkxk; d v/; {k rFkk jkt Lo i fj"kn u t kjh fd; k

NOTIFICATION

January 29, 2013

### Uttarakhand Electricity Regulatory Commission

#### (Release of new LT Connections, Enhancement and Reduction of Loads) Regulations, 2013

**No. F-9(12)/RG/UERC/2013/1466--**In exercise of powers conferred under Section 181 read with Section 45 3(b) and Section 46 of the Electricity Act 2003, and all powers enabling it in that behalf, Uttarakhand Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations:

#### 1. Short title, Commencement and Application:

- (1) These Regulations may be called the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Release of new LT Connections, Enhancement and Reduction of Loads) Regulations, 2013.
- (2) These Regulations shall come into force on the date of the publication in the official Gazette. However, the Applicants, who have deposited the requisite charges, prior to notification of these new regulations, shall be covered under the old Regulations namely UERC (Release of new LT Connections, Enhancement and Reduction of Loads) Regulations, 2007.
- (3) These Regulations extend to the whole State of Uttarakhand.
- (4) These regulations will apply to only LT connections having load upto 75 kW/88kVA/100BHP and will cover grant of new connections and of increase or decrease of loads already sanctioned.
- (5) With the coming into force of these Regulations, UERC (Release of new LT Connections, Enhancement and Reduction of Loads) Regulations, 2007 shall stand repealed.

#### 2. Definitions :

In these Regulations, unless the context otherwise requires:

- (1) "Developer/Builder" means a person or company or organisation or authority that undertakes construction of residential, commercial or industrial complex ;
- (2) "Low Tension (LT)" means the voltage of 230 volts between phase and neutral or 400 volts between any two phase under normal conditions subject to the percentage variation permissible under the Electricity Rules;
- (3) "Outstanding dues" means all dues against a premises at the time of disconnection plus late payment surcharge subject to section 56(2) of the Electricity Act, 2003;

- (4) "Rules" mean the Indian Electricity Rules 1956 or their successor rules framed under Section 53 of the Electricity Act, 2003;
- (5) All words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Electricity Act, 2003 shall have the meaning assigned to them in the said Act.

### 3. Conditions for grant of connections :

- (1) The licensee shall prominently display on its website and in all its offices details of places where Applications for new connection are accepted on its behalf, the detailed procedure for grant of a new connection and the complete list of documents required to be furnished along with such Applications. Normally no document, which has not been so listed, will be required and shall be asked for. Initial security amount, cost of service line charges, normative overhead line charges and normative cost of transformer to be deposited by the Applicant in accordance with Tables 1 to 4 given in regulation 5(10) of these Regulations shall also be prominently displayed.
- (2) Where the Applicant has purchased an existing property whose electricity connection has been disconnected, it shall be the duty of the Applicant to verify that the previous owner has paid all dues and has obtained "no-dues certificate" from the Licensee. In case such "no-dues certificate" has not been obtained by the previous owner, the new owner, before purchase of property, may approach the concerned officer of the Licensee for such a certificate. The licensee shall acknowledge the receipt of such request and shall either intimate in writing the dues outstanding on the premises, if any, or issue the "no-dues certificate" within one month from the date of receipt of such Application. In case the Licensee does not intimate the outstanding dues or issue the "no-dues certificate" within this time, new connection on the premises shall not be denied on ground of outstanding dues of the previous consumer. In such an event, the licensee shall have to recover his dues from previous consumer as per provisions of law.
- (3) Where a property has been legitimately sub-divided, the outstanding dues for the consumption of electricity on earlier undivided property, if any, shall be divided on pro-rata basis based on area of each sub-divided property.

A new connection to any portion of such sub-divided premises shall be given only after the share of outstanding dues attributed to such legitimately sub-divided premises is duly paid by the Applicant. A Licensee shall not refuse connection to an Applicant only on the ground that dues on the other portion(s) of such premises have not been paid, nor shall the Licensee demand, record of last paid bills of other portion(s) from such Applicant.

- (4) In case of demolition & reconstruction of the entire premises or the building, the existing connection shall be surrendered and agreement terminated. Meter and service line will be removed, and a new connection shall be taken for the reconstructed building, after clearing all dues on the old premises. Temporary power supply from the existing connection shall not be allowed for construction purpose in such cases.
- (5) A connection will be given to a new consumer only with a correct energy meter as provided in the Central Electricity Authority (Installation & Operation of Meters) Regulations, 2006 and the same shall be installed as prescribed in the said regulations.
- (6) In case of Application for Load upto 4 kW

(a) If the premises is beyond 40 meters from licensee's existing 3 phase LT distribution main:

The licensee shall extend the existing 3 phase LT distribution main by constructing 3 phase 5 wire LT distribution main only and the Applicant shall have to pay, in addition to fixed service line charges, normative charges of LT distribution main, as per Table 1 of Regulation 5(10), depending upon the length of the line required for releasing such connection. Except for rural hilly villages having population less than 10000 as per census 2011 where the licensee may extend the aforesaid 3 phase LT distribution main by constructing single phase LT distribution main for giving such connection in these villages.

(b) If the premises is beyond 40 meters from licensee's existing single phase or two phase LT distribution main:

The extension of existing LT distribution main will be done by constructing single phase or 2 phase LT distribution main by the licensee and the Applicant shall have to pay, in addition to fixed service line charges, normative charges of LT distribution main, as per Table 1 of Regulation 5(10), depending upon the length of the line required for releasing such connection.



- (7) In case of Application for Load above 4 kW and upto 25 kW
  - (a) If the existing LT distribution main is of single phase or 2 phase, the licensee shall carry out the necessary conversion of such LT distribution main by 3 phase 5 wire LT distribution main at its own cost for releasing such connection.
  - (b) If the premises is beyond 40 meters from licensee's existing 3 phase LT distribution main, the licensee shall carry out extension by constructing 3 phase 5 wire LT distribution main and the Applicant shall have to pay, in addition to fixed service line charges, normative charges, as per Table 2 of Regulation 5(10), depending upon the length of the line required for releasing such connection.
- (8) In case of Application for Load above 25 kW, the connection shall be released only through HVDS system and the Applicant shall have to pay normative charges as per Table 3 of Regulation 5(10).
- (9) In case of PTW connection, if the extension of the LT distribution mains and /or HT main including installation of Distribution Transformer is required for releasing the PTW connection, then the Applicant shall have to pay in addition to fixed service line charges, normative charges of such works, as per Table 4 of Regulation 5(10), depending upon the length of the line required for releasing such connection.
- (10) No Single Point Bulk Supply connection shall be released on LT.

#### 4. Application for new connection :

Any Application for release of a new connection shall be submitted along with documents listed below and shall be processed by the licensee as given hereafter:

- (1) A prospective consumer desirous of obtaining a new electric connection shall make an Application to the licensee for this purpose on the prescribed Application form given in Annexure 1.
- (2) Prescribed Application form can be obtained free of cost from licensee's Sub-divisional office or any other office of the licensee or the same can be download from the official website of the licensee viz. [www.upcl.org](http://www.upcl.org) or even photocopied. The duly filled form can be submitted at the concerned nearest Sub-division/Division office of the licensee.
- (3) The documents required to be submitted along with the Application form are given below:

##### [a] Proof of Ownership or Occupancy :

The Applicant shall submit any one of the following documents as proof of ownership or occupancy over premises for which the connection is required –

- (i) Copy of sale deed or lease deed or copy of the khasra or khatauni (inclusion of Applicant's name in the khasra or khatauni shall be sufficient for this purpose) or
- (ii) Registered General Power of attorney or
- (iii) Municipal tax receipt or Demand notice or any other related document or
- (iv) Letter of allotment.
- (v) An Applicant who is not an owner but an occupier of the premises shall alongwith any one of the documents listed at (i) to (iv) above also furnish a no objection certificate from owner of the premises.

Provided that in case the Applicant is unable to submit any of the document listed at (i) to (v) above, then the Applicant shall be charged thrice (except for BPL consumers) the amount of security as per Tables 1 to 4 given in Regulation 5(10). The owner of the premises, if different from the Applicant, shall not be liable for payment of any dues against such connection.

##### [b] Identity Proof :

- If the Applicant is an individual, copy of any one of following documents shall be furnished as identity proof



- (i) Electoral identity card or
- (ii) Passport or
- (iii) Driving license or
- (iv) Photo ration card or
- (v) Photo identity card issued by Government Agency or
- (vi) Certificate from village Pradhan or any village level Govt. functionary like Patawari/Lekhpal/Primary school teacher/in-charge of primary health centre etc.
- If the Applicant is a company, trust, school/college, government department etc, Application shall be signed by competent authority, like Branch Manager, Principal, Executive Engineer along with relevant resolution/authority letter of the institution concerned etc.

**[c] Undertaking :**

An undertaking in the format given in Annexure 1.1 certifying that the wiring and other electrical works in the premises has been done in accordance with the provisions of the applicable Act /Rules & Regulations.

- (4) On receipt of duly filled Application form from the Applicant, the authorized officer of the licensee shall check the Application form and deficiencies, if any, observed in the Application shall be got rectified from the Applicant immediately.
- (5) No Application for new connection shall be returned by the licensee for reasons such as "technically not feasible" or due to any material constraint.

**5- Processing of an Application by the licensee :**

- (1) On receipt of an Application form, the licensee shall register the Application by putting a Unique Application Number both on the Application form and the Acknowledgement form and thereafter, issue dated acknowledgement of the same to the Applicant.
- (2) The licensee shall inspect and test the Applicant's installation, as required of him under Rule 47 of IE Rule 1956, in the presence of the Applicant or his representative within 5 days from the date of receipt of the Application form. Testing of installation shall be done as per procedure laid down in Rule 48 of IE Rules 1956 and the inspecting officer shall maintain a record of test results obtained in the form given at Annexure 1.2 as required of him under Rule 47 of IE Rule 1956. The Licensee shall also ascertain the requirement of extension of distribution mains i.e. overhead line and other associated works as per the Regulations.

If required, the licensee shall conduct the route survey and prepare estimate of the works in accordance with the Regulations within 10 days from the date of receipt of the Application form.

- (3) If upon inspection, the Licensee finds any defect, like the installation having not been completed or bare ends of conductor or joints having not been properly covered with insulating tape or that the wiring is of such nature that it is dangerous to life /property etc., he shall intimate the same to the Applicant on the spot under proper receipt in the form given at Annexure 1.2
- (4) Licensee shall also record correct and full address of the premises, if not provided in the Application, along with land mark near the property and also pole number from where service connection is proposed to be given. This information is necessary for future meter reading and billing.
- (5) The Applicant shall get all the defects removed within 15 days and inform the licensee in writing under acknowledgement. In case Applicant fails to remove such defects or fails to inform the licensee about removal of the defects, the Application shall stand lapsed and Applicant will have to apply afresh.
- (6) Upon receipt of information from Applicant about removal of defects, the Licensee shall re-inspect and test the installations within 5 days from receipt of such information and if the defects pointed out earlier are found to persist, the licensee shall again record the same in

the form given at Annexure 1.2 and hand over a copy of the same to Applicant or his representative available on site. The Application shall then stand lapsed and Applicant shall be informed accordingly in writing under acknowledgement. If the Applicant feels aggrieved by this action of the licensee, he may appeal to the Electrical Inspector, whose verdict in the matter will be final and binding.

- (7) Licensee shall also ascertain whether any dues are outstanding on the premises, and if so, the licensee shall issue a demand note within 5 days from date of receipt of Application form giving full details of such outstanding amount. The Applicant shall be required to deposit outstanding dues within 15 days failing which his Application shall lapse and the Applicant shall be informed accordingly in writing under acknowledgement.
- (8) If on inspection no deficiency is found or the deficiencies are found to have been removed and there are no outstanding dues or the same have been cleared, the Licensee shall sanction the load, as applied for, by the Applicant (except for Residential/Non Residential Complex, Multiplex, Malls etc. where the load shall be determined as per the norms specified in Annexure 3 of these Regulations) and intimate the same to the Applicant in writing within 5 days of receipt of Application form.
- (9) In case Applicant does not receive any deficiency note or demand note for the outstanding dues within 5 days from the date of Application, the load, as per sub-regulation hereinabove, shall be deemed to have been sanctioned and licensee shall not deny grant of the connection on these grounds.
- (10) Within 5 days from sanction of the load, the licensee shall inform estimate of the works based on the prescribed charges given in tables below and the Applicant shall deposit the aforesaid charges in cash or through demand draft.

**Table-1: Service Line charges, Overhead line charges and Initial security for loads upto 4 kW**

Sl. No.	Contracted Load	Service Line Charges & Overhead line charges			Initial security( Rs./kW)		
		Service line charges (Rs.)		Overhead line charges if premises is beyond 40 meters of the licensee's existing LT distribution main (Rs.)	Domestic	Non-Domestic	Industrial
		Overhead	Under-ground				
1.	BPL consumers	100	-	300	100	-	-
2.	Upto 4 kW	600	1200	Rs. 1000 per 10 meters or part thereof	400	1000	1000

**Table 2: Service Line charges, Overhead line charges and Initial security for load above 4 kW and upto 25 kW**

Sl. No.	Contracted Load	Service Line Charges & Overhead line charges			Initial security( Rs./kW)		
		Service line charges (Rs.)		Overhead line charges if premises is beyond 40 meters of the licensee's existing LT distribution main (Rs.)	Domestic	Non-Domestic	Industrial
		Over-head	Under-ground				
1.	Above 4 kW and upto 10 kW	1500	3000	Rs 3000 per 10 meters or part thereof	400	1000	1000
2.	Above 10 kW and upto 25 kW	2500	5000				

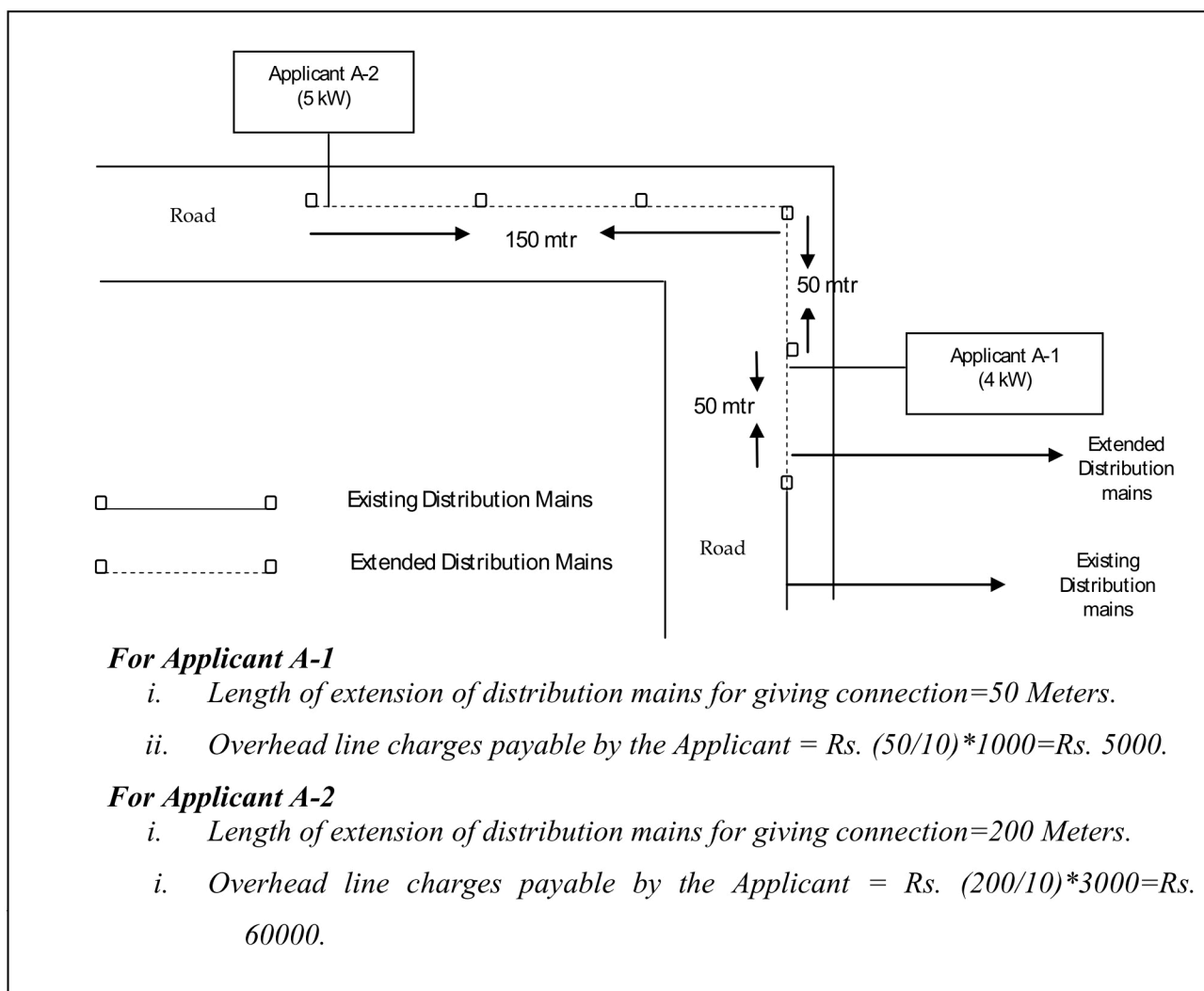
**Table 3: Service Line charges, Charges for construction of Overhead 11 kV line/ Substation/Increasing capacity of Transformer and Initial security for load above 25 kW and upto 75 kW (irrespective of the distance of the consumer's premises from the HT/LT Distribution Mains)**

S. No.	Contracted load	Service Line Charges, Charges for construction of Overhead 11 kV line/ Substation/Increasing capacity of Transformer			Initial security( Rs./kW)		
		Service line charges (Rs.)		Charges for construction of Overhead 11 kV line/Substation/Increasing capacity of Transformer (Rs.)	Domestic	Non-Domestic	Industrial
		Overhead	Underground				
1	11 kV line Cost						
	Above 25 kW and upto 50 kW	4000	8000	Rs. 3000 per 10 meter or part thereof.	400	1000	1000
	Above 50 kW and upto 75 kW	5000	10000				
2	11 kV Substation Cost						
	Above 25 kW upto 50 kW	Construction of 63 kVA s/s		125000	-		
	Above 50 kW upto 75 kW	Construction of 100 kVA s/s		175000			
3	Increasing capacity of Transformer						
	63 kVA to 100 kVA	-		50000	-		

**Table 4: Service Line charges, overhead line charges and Initial security for Private Tube Wells (PTW) having load above 5 B.H.P. and upto 20 B.H.P.**

S. No	Contracted load	Service line charges (Rs.)	Charges for extension of existing LT distribution mains and /or HT main including installation of Distribution Transformer (Rs.)	Initial security (Rs/H.P.)
1	5 B.H.P. to 20 B.H.P.	600	Rs. 500 per 10 meters or part thereof	100

- (11) Applicant shall be liable to pay charges for the overhead line, as applicable in accordance with the above Tables, for that length of the LT/HT Distribution Mains actually extended for giving supply to such Applicant.

**Illustration: Calculation of the length of extension of the existing Distribution main**

(12) The licensee shall be under obligation to energize the connection through a correct meter within 30 days from the :

- date of Application if no defects or outstanding dues are found.
- date of intimation of removal of defects or liquidation of outstanding dues or the date of Application whichever is later.

**Explanation**—For the purpose of this Regulation, “Application” means the Application complete in all respects in the appropriate form along with documents showing payment of necessary charges and other compliances.

- If a new connection is required in which the licensee is required to extend its distribution mains or lay new distribution mains or commission a new substation then the licensee shall inform such Applicant the time required to give the supply and the same shall not exceed:
  - 60 days if only extension of distribution mains is required.
  - 90 days if commissioning a new substation is also required.
  - 180 days if commissioning of new 33/11 kV substation is required.
- If the licensee fails to provide connection to an Applicant within the period specified above, he shall be liable to pay penalty @ Rs.10 per Rs 1000 (or part thereof) of the amount deposited by the Applicant subject to a maximum of Rs. 1000 for each day of default.

- (15) Licensee shall submit to the Commission monthly division-wise report containing details of number of connections that were not energised within specified period and shall also deposit with it the penalty accrued on account of such defaults.
- (16) In case his connection has not been energized as per these regulations, an Applicant may lodge a complaint about it with the Consumer Grievance Redressal Forum of respective distribution zones giving full details such as date of Application, date of inspection by licensee etc.

6. Apart from the charges prescribed in the Tables 1 to 4 above, no other charges such as cost of meter, cost of miscellaneous material, extra cable, processing fees etc. shall be payable by the Applicant of a new connection.

**7. New Electricity Connection in Residential/Non-Residential Complex, Multiplex, Malls etc. to be constructed by Developer/Builder :**

- (1) The responsibility of creating required distribution network within such complex from the installed distribution transformer onwards and upto to the point of connection to the installation of each consumer within such complex shall be that of the developer/ builder who has constructed such complex.
- (2) Based on the normative load to be calculated as per details given in Annexure 3, the capacity of distribution transformer or both 33/11 kV transformers and distribution transformer, as the case may be, to be installed shall be determined by the licensee. The cost of 33/11 kV transformer/ distribution transformer, as the case may be, and associated protection gear shall be borne by the concerned developer/builder. The cost of extending 11 kV or 33 kV line, as the case may be upto the transformer installation shall also be paid by the developer/builder. For this purpose, the cost will be estimated by the distribution licensee and such cost will be payable by the developer/builder subject to recovery/ refund of additional amount on completion of the work.

The developer/builder shall have the option to create the required infrastructure i.e. power/distribution transformer sub-station and LT/HT lines alongwith associated equipments, on its own through a licensed contractor, as per the specifications of the licensee, by paying supervision charges to the licensee at the rate of 15% to be levied on estimated material cost, labour cost and shall not include establishment cost.

- (3) At the time of seeking new connection, the individual Applicant of such complex, shall be required to pay service line charges and initial security deposit only as per tables given in Regulation 5(10) above based on the applicability.
- (4) The land for installation of power/distribution transformers shall be provided by such developer/builder to the distribution licensee, free of cost.

**8. Procedure for Enhancement / Reduction in Sanctioned Load :**

- (1) Consumers shall be permitted to reduce their contracted load anytime only once in a financial year. However, no restriction shall apply on enhancement of load.
- (2) For this the consumer will apply to the licensee in the form given at Annexure 2 and available free of cost at licensee's Sub-division office alongwith the proof of payment of the latest bill. The form can also be downloaded from the licensee's website.
- (3) The licensee shall register the Application by putting a Unique Application Number both on the Application form and the Acknowledgement form. Thereafter, a written and dated acknowledgement shall be given to the Applicant for receipt of his Application.
- (4) A consumer seeking enhancement in load shall pay initial security applicable to the total enhanced load and if the fixed service line/overhead line /meter etc. is also required to be changed, then the consumer shall have to pay charges as per tables 1 to 4 of Regulation 5(10) above depending upon the applicability. Such charges shall be reduced by the

depreciated cost of the equipment removed, as above, if the cost had been borne by the consumer and they are reusable by the licensee and security amount already paid towards the existing load shall be duly adjusted.

- (5) If the reduction in load sought by the consumer involves change of the existing transformer/ meter etc. then the consumer shall pay to the licensee charges as per Tables 1 to 4 of Regulation 5(10) above depending upon the applicability. Such charges shall be reduced by the depreciated cost of the equipment removed, as above, if the cost had been borne by the consumer and they are reusable by the licensee and the difference between initial security deposit required for the reduced load and that already deposited shall be adjusted in the bills within the next two billing cycles.
- (6) While considering the request for load reduction, the licensee shall first verify the said consumer's actual consumption profile. In case the actual consumption pattern indicates that the load actually utilized in the past is higher than that being demanded, reduction so sought shall not be permitted and the Applicant shall be informed accordingly. Example:

**For installations where Electronic meter with MDI has been installed:**

<i>Load Category</i>	<i>Industrial</i>
<i>Sanctioned Load</i>	<i>50 kVA</i>
<i>Load Reduction Requested</i>	<i>35 kVA</i>
<i>Max. demand during last 12 months</i>	<i>40 kVA</i>

Since Max Demand during last 12 months as indicated by MDI was higher than requested reduced load, request not to be acceded to.

**For Installations where meters do not have MDI**

<i>Load category</i>	<i>Domestic</i>
<i>Sanctioned load</i>	<i>7 kW</i>
<i>Load reduction requested</i>	<i>4kW</i>
<i>Max. Monthly consumption during last 12 months</i>	<i>600 kWh</i>
<i>Normative consumption for domestic category*</i>	<i>100 kWh/kW</i>
<i>Load calculated on normative consumption</i>	<i>600/100 = 6 kW</i>

*\* Normative consumption as indicated for provisional billing in the tariff order*

Since average load during last 12 months was higher than requested reduced load, request for load reduction not to be acceded.

- (7) The sanctioned load shall be enhanced/reduced within 30 days after receipt of the Application requiring such enhancement/reduction. In case the enhancement/reduction in load is not affected within the specified period, a penalty of Rs. 500 shall be payable by licensee.

**9. Savings :**

- (1) Nothing in these regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner, as it considers just and appropriate.
- (2) If any difficulty arises in giving effect to these regulations, the Commission may, of its own motion or otherwise, by an order and after giving reasonable opportunity to those likely to be affected by such order, make such provisions, not inconsistent with these regulations, as may appear to be necessary for removing the difficulty.
- (3) The Commission, for reasons to be recorded in writing, may relax or vary any of the provisions of these regulations on its own motion or on an Application made before it by an interested person.

**Annexure 1****Application Form for New Connection**

Photograph of  
the Applicant

**(For office use only)**

Name of Division	
Name of Sub-division	
Unique Application Number	
Date of receipt	

**(To be filled by the Applicant)**

1	Applicant's Name (In Capital letters)		
2	Father's/Spouse Name		
3	Address at which supply is required	House/Plot	
		Street	
		Colony/Area	
		District	
Telephone No. (if any)		Mobile (If any)	
<b>If Applicant is a company or organization or association</b>			
4	Permanent Address	House/Plot	
		Street	
		Colony/Area	
		District	
Telephone No. (if any)		Mobile (if any)	
<b>If Applicant is tenant or occupier</b>			
5	Address of Owner of property	House/Plot	
		Street	
		Colony/Area	
		District	
Telephone No. (if any)		Mobile (if any)	
6	Load applied for (in kW)		
7	Plot Size and Built up area (Sq Meters) (for Domestic & non-domestic connection only)		
8	Intended Usage	<b>Tick applicable:</b> a. Domestic b. Non-Domestic c. Industrial d. Private Tube Well	
9	If any electricity connection is existing at the premises		Yes/No
11.	If yes give the following details:		
	a) Service connection number		
	b) Book number		
12	Nearest landmark Pole No./Feeder pillar No./Nearest house number ( to be filled by the licensee)		



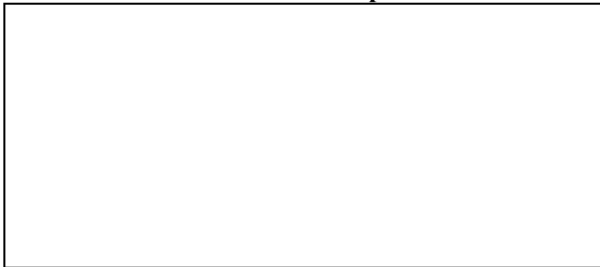
13	List of Document attached	1	Identity/Address Proof (copy of anyone of the following), Tick any one: a. Electoral Identity Card b. Passport c. Driving License d. Photo Ration Card e. Photo identity card issued by Government Agency. f. Certificate from village Pradhan or any village level Govt. functionary like Patawari/Lekhpal/ Primary school teacher/in-charge of primary health centre etc.	
		2	Proof of Ownership/Occupancy (copy of anyone of the following), Tick any one: a. Copy of sale deed or lease deed or copy of the khasra or khatauni or b. Registered General Power of attorney or c. Municipal tax receipt or Demand notice or any other related document or d. Letter of allotment. e. An Applicant who is not an owner but occupier of the premises shall alongwith any of the documents listed in (a) to (d) above also furnish a no objection certificate from owner of the premises.	
		3	Declaration/Undertaking by Applicant in the prescribed format	

Date :

Signature

Acknowledgement**Received Application for new connection for electricity as per details given below:**

- 1) Unique Application Number \_\_\_\_\_
- 2) Name of Applicant \_\_\_\_\_
- 3) Address where \_\_\_\_\_  
Connection is required \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 4) Load Applied for \_\_\_\_\_

**Rubber Stamp**

Signature of UPCL representative

Name and Designation

**Annexure 1.1****DECLARATION /UNDERTAKING**

I, \_\_\_\_\_ son of \_\_\_\_\_ Resident of \_\_\_\_\_ (hereinafter referred as "Applicant", which term shall mean and include executors, administrators, heirs, successors and assigns), do hereby swear and declare as under:

Or

The \_\_\_\_\_, a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 having its registered office at \_\_\_\_\_ (hereinafter referred as "Applicant", which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof, include its successors and assigns), do hereby swear and declare as under:

THAT the Applicant is a lawful occupant of the premises at \_\_\_\_\_ in support of which the Applicant has enclosed a proof of occupancy.

THAT the Applicant has requested UPCL to provide a service connection at the above-mentioned premises in the Applicant's name for the purpose mentioned in the Application form.

THAT in furnishing the Declaration, the Applicant has clearly understood that should the above statements prove to be false or incorrect at any later stage, the UPCL shall have every right to disconnect supply to the Applicant without any notice and above right to adjust dues against Consumer Security Deposit.

THAT the Applicant hereby agrees and undertakes:

1. To indemnify UPCL against all proceedings, claims, demands, costs, damages, expenses that UPCL may incur by reason of a fresh service connection given to the Applicant.
2. That all the Electrical Works done within the premises are as per Indian Electricity Rules and has been carried out by a licensed electrical contractor (In case Applicant is owner and wiring in the premises is new)

Or

That all the Electrical Work done within the premises are as per Indian Electricity Rules to the best of our knowledge (where Application is for reconnection or Applicant is occupier of the premises)

3. UPCL is indemnify against any loss accrued to the Applicant on this account. Further, Applicant agrees that if there is any harm/loss to the property of UPCL due to the fault in Electrical work within the premises of Applicant, all the liabilities shall be borne by the Applicant.
4. To pay the Electricity consumption bills and all other charges at the rates set out in UPCL's Tariff Schedule and Miscellaneous charges for supply as may be in force from time to time, regularly as and when the same becomes due for payment.
5. To deposit the additional Consumption deposit as revised by UPCL from time to time based on the consumption of the Applicant in preceding year.
6. To abide by the provisions of the Electricity Act, 2003, Electricity Supply Code, Tariff Orders and any other Rules or Regulations notified by UERC, as applicable from time to time.
7. That UPCL shall be at liberty to adjust the electricity consumption charges along with any other charges against the Consumer Security Deposit paid by the Applicant, in the event of termination of the agreement prior to expiry of the contracted period or in case of any contractual default.
8. To be responsible for safe custody of Meters, CTs, Cables etc. provided by UPCL and in case, there is any damage to equipment due to the reasons attributable to Applicant the same shall be chargeable to the Applicant. Further, all repercussions on account of breakage of seals of meters etc. or Direct/Dishonest Abstraction of energy shall be to the account of Applicant, as per the existing laws.

9. To allow clear and un-encumbered access to the meters for the purpose of meter reading and its checking etc.
10. That the Applicant would let UPCL disconnect the Service connection under reference, in the event of any default, non-compliance of statutory provisions and in the event of a legally binding directive by Statutory Authority(s) to effect such an order. This shall be without prejudice to any other rights of UPCL including that of getting its payment as on the date of disconnection.
11. That UPCL shall not be held responsible for any interruption or diminution of supply of Electricity.
12. All the above declaration given by the Applicant shall be construed to an Agreement between UPCL and the Applicant.

Signature of the Applicant

Name of the applicant

SIGNED AND DELIVERED  
In presence of witness

Name of Witness

**Annexure 1.2****Test Result Report****(refer rule 47 & 48 of IE Rules 1956)**

(To be filled by representative of the licensee)

Result of Insulation Resistance (to be measured on applying a pressure of 500 volts for one minute between phase conductor and earth) -

Phase-1 & EarthPhase-2 & EarthPhase-3 & Earth

(i) Between Phase and Earth

Caution: Insulation Resistance between phase and neutral or between phases shall not be measured when any of consumer's appliances, such as fans, tubes, bulbs, etc. is in circuit as results of such test would give resistance of appliance and not the insulation resistance of installation.

Certified that an Earth Terminal as required under Rule 33 of IE Rules 1956 has been provided by UPCL and this terminal has been connected with UPCL's earthing system.

Following deficiencies have been found in your Electrical installation. You are requested to remove them within 15 days i.e. by \_\_\_\_\_ and inform UPCL failing which your request for new connection would lapse:

- 1- \_\_\_\_\_
- 2- \_\_\_\_\_
- 3- \_\_\_\_\_
- 4- \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Signature of licensee representative

Name and Designation

**(To be filled by Applicant)**

The testing of the premises has been carried out by licensee in my presence and

\*I am satisfied with the testing

\*I am not satisfied with the testing and may file an appeal with Electrical Inspector

It is also certified that UPCL has\*/has not\* provided an Earth Terminal as per Rule 33 of IE Rules 1956 at the premises and this earth terminal has\*/has not\* been connected to UPCL's earthing system.

Date \_\_\_\_\_

Signature of Applicant

\* Strike out which is not applicable

## Annexure 2

## Application for Load Enhancement/Reduction

Photograph of the  
Applicant

[illegible]

Load Enhancement		Load reduction	
Existing Sanctioned Load		Existing Sanctioned Load	
Enhanced load requested		Reduced Load requested	

1	Consumer No.													
1a	Book No.													
2	Consumer Name													
3	Address at which supply is provided	House/Plot												
		Street												
		Colony/Area												
		District												
	Telephone No.								Mobile No.					

Date: \_\_\_\_\_

Signatures of Applicant

**Annexure 3****Procedure for Determination of Contracted Load in case of New Electricity Connection in Residential/Non-Residential Complex, Multiplex, Malls etc. to be constructed by Developer/Builder****Load****(i) Residential Use**

For every 400 sq. ft. built up area or part thereof

- |  |         |
|--|---------|
| a. In Municipal Corporation (Nagar Nigam) area | 1 KW    |
| b. In Municipal Board (Nagar Palika) area      | 0.75 KW |
| c. In Nagar Panchayat /Gram Panchayat area     | 0.50 KW |

**(ii) Non-Residential Use**

- |   |      |
|---|------|
| a. For every 200 sq. ft. built up area or part thereof                | 1 KW |
| b. 1000 sq.ft. built up area or part thereof for shed /godown /school | 1 KW |

**Note:** The load of the common facilities like lift, water pump, street lights etc. shall be taken as declared by the Developer/Builder.

By Order of the Commission,

NEERAJ SATI,

*Secretary,*

Uttarakhand Electricity Regulatory Commission.